

प्रेषक,

पी०क०० महानि  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन

संवा में

निदेशक,  
पंचायतीराज  
उत्तराखण्ड, देहरादून

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग देहरादून दिनांक २५ जुलाई, 2007  
विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु विभिन्न वर्चनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 187/XII/2006/82(25)/2003, दिनांक 30 मार्च, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अन्तर्गत पंचायतीराज अधिकार इत्यादि वर्चनबद्ध मानक मदों में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र. सं.	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में बजट प्राप्तिधान	शासनादेश संख्या 187 दिनांक 30.03.07 के द्वारा जा अवमुक्त धनराशि	जा रही धनराशि
1.	01-वेतन	8659	2480	6179
2.	03-महगाइ भत्ता	5195	1302	3893
3.	04-यात्रा व्यय	300	183	117
4.	06-अन्य भत्ता	953	303	650
5.	08-कार्यालय व्यय	500	217	283
6.	09-विद्युत देय	140	56	84
7.	10-जलकर/जल प्रभार	15	14	1
8.	13-टेलीफोन व्यय	150	98	52
9.	15-गाडियाँ का अनुरक्षण एवं पट्रोल आदि की खरीद	300	133	167
10.	48-महगाइ वेतन योग	4330	1240	3090
		20542	8026	14516

(रु० एक करोड़ पैतालीस लाख सोलह हजार भारत)

- उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जावेगा तथा सम्बद्धिता अधिकार इत्यादि व्यवस्थकालानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय।
- उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक नुस्तन कर आवश्यकालानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाय।
- इन क्रमबद्ध तालूकार्थी के लिए ही व्यय किया जायेगा।
- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/ जारी हान वाल मित्रव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाव तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

6. निर्माण कार्य एवं सामग्री का हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगमन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/ प्राविधिक स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर जी जाय तथा धनराशि का आहरण आदश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय ।

7. उक्ता आवृत्ति धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र-वी०एम०-१३ पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

8. इस सम्बन्ध में हाने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-१९ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-२५१५-अन्य ग्राम विकास कार्बकम-आयोजनेतर-१०१-पंचायतीराज-०३ पंचायतीराज अधिकारी की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे ढाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ५९९/ XXVII(1)/2006, दिनांक १२ जुलाई, २००७ के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,  
( पी०के० महान्ति )  
सचिव ।

संख्या ४३७ / XII / ०७ / ८२(२५) / २००३ तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. चरिक कोषाधिकारी, / समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त संचारे उत्तराखण्ड 23 लक्षी रोड देहरादून ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून ।
6. निजी समिति, मुख्य समिति, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य समिति महोदय के आयलोकनार्थ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन ।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन समितिवालय देहरादून ।
9. गार्ड फाईल ।

आड्डा स  
२००८/११/४  
(ज०प००ज०शी )  
उप सचिव ।